National Journal of Multidisciplinary Research and Development
ISSN: 2455-9040; Impact Factor: RJIF 5.22
Received: 06-08-2019; Accepted: 09-09-2019
www.nationaljournals.com
Volume 4; Issue 4; October 2019; Page No. 17-20

बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की समस्याएँ

प्रशान्त कुमार
शोधार्थी, वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग, ल0ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार, भारत

सारांश
बिहार एक कृशि प्रधान राज्य है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से राज्य की तकदीर बदल सकती है। राज्य के बंटवारे के समय खनिज संपदा से जुड़े उद्योग झारखंड के हिस्से जाने के बाद पूरे बिहार में खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने की बात उठी थी, लेकिन इस दिषा में कारगर कदम नहीं उठाए जा सके। तकनीक, पैकेजिंग व बाजार की कमी से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जूझ रहा है। इसके अलावा इसे षुरू करने वाले युवा उद्यमियों को सरकार की ओर से पर्याप्त मदद नहीं मिल पाती है। सरकार से पर्याप्त सहयोग मिलने पर बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आर्थिक क्रांति ला सकती है।

मूल शब्द: बिहार, भारतीय, प्रसंस्करण, सरकार, क्रांति

प्रस्तावना
भारतीय अर्थव्यवस्था अति प्राचीनकाल से कृशि आधारित रही है। प्राचीनकाल में कृशि और पशुधन हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। यही कारण है कि भारत का स्वरूप एक कृशि प्रधान राश्ट्र के रूप मे उभरा। अर्थव्यवस्था के निर्धारण में कृशि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देष में कृशि की प्रधानता रही और कृशि ही हमारी अर्थव्यवस्था की धुरी रही। तभी तो हमार यहाँ 'उत्तम कृशि, मध्यम बान, निकृश्ट चाकरी, भीख निदान' की कहावत प्रचलित हुई। कृशि को सर्वोत्तम बताया गया। देष की अर्थव्यवस्था में कृशि की महत्वपूर्ण भूमिका बनी हुई है। ऐसा अनेक कारणों से है। सबसे प्रमुख कारण यह है कि आज भी भारत की कार्यकारी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा रोजगार के लिए कृशि पर ही निर्भर करता है। यह भारत में जीवन निर्वाह का सबसे बड़ा माध्यम है। जिस देष की 80 प्रतिषत जनसंख्या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृशि पर निर्भर होगी, उस देष की अर्थव्यवस्था में कृशि के महत्व को सहजता से समझा जा सकता है। आज भी भारत में कृशि कुल श्रमषक्ति के 57 प्रतिषत को राजगार उपलब्ध करवाती है।

उद्योगों के लिए भी भारतीय कृशि का महत्व कम नहीं है। हमारे प्रमुख उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति कृशि से होती है। तमाम उद्योग तो ऐसे हैं, जो सीधे–सीधे कृशि पर आधारित है मसलन वनस्पति व बागान उद्योग, सूती व पटसन वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, डेयरी उद्योग आदि ऐस उद्योग हैं, जिनका सीधा सम्बन्ध कृशि से है। इसी प्रकार अनेक उद्योग ऐसे हैं, जिनकी निर्भरता परोक्ष रूप से कृशि पर बनी हुई है। तमाम सारे लघु उद्योग भी कृशि पर ही केन्द्रित है। सभी को कच्चे माल के लिए कृशि पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इस तरह से अर्थव्यवस्था के निर्धारण में भारतीय कृशि न सिर्फ निर्णायक व महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बल्कि औद्योगिक उन्नति को मजबूत आधार भी प्रदान करती है। आंकड़ों से पता चलता है कि विनिर्माण क्षेत्र में होने वाली आय का 50 प्रतिषत हिस्सा हमें कृशि क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। पिछले कुछ वर्शों में देष में खाद्य–प्रसंस्करण उद्योग तेजी से फले–फूले हैं, जिन्हें कृशि क्षेत्र ने ही संबल प्रदान किया है। हमारे देष में परम्परागत उद्योगों का आधार कृशि ही रही है, जिसने सदैव अर्थव्यवस्था के निर्धारण में महत्वपूर्ण निभाई (द्विवेदी, 2014)।

बिहार एक कृशि प्रधान राज्य है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से राज्य की तकदीर बदल सकती है। राज्य के बंटवारे के समय खनिज संपदा से जुड़े उद्योग झारखंड के हिस्से जाने के बाद पूरे बिहार में खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने की बात उठी थी, लेकिन इस दिषा में कारगर कदम नहीं उठाए जा सके। तकनीक, पैकेजिंग व बाजार की कमी से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जूझ रहा है। इसके अलावा इसे षुरू करने वाले युवा उद्यमियों को सरकार की ओर से पर्याप्त मदद नहीं मिल पाती है। सरकार से पर्याप्त सहयोग मिलने पर बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आर्थिक क्रांति ला सकती है।

कृशि आधारित उद्योग–धंधे
सामजिक–आर्थिक जनगणना के जो आंकड़ें आए हैं, वे सिर्फ यही बताते हैं कि अच्छे दिन अभी हमारे गाँवों में नहीं पहुंचे हैं। देष के कुल 24.39 करोड़ घरों में से 17.91 करोड़ ग्रामीण घर हैं। इनमें से करीब आधे घर, यानी 48.52 फीसदी घर किसी न किसी तरह के अभाव से जूझ रहा है। गाँवों में हर तीसरा परिवार भूमिहीन है और आजीविका के लिए षारीरिक श्रम पर निर्भर है। गाँवों में 2.37 करोड़ परिवार एक कमरे के कच्चे घरों में रहते हैं, वहीं 51.14 फीसदी परिवार दिहाड़ी मजदूरी पर निर्भर है। इनके बाद खेती पर निर्भर परिवारों का स्थान है, जो 30.10 फीसदी है। 14.01 प्रतिषत परिवार अन्य स्त्रोतों पर निर्भर है। इसके अलावा, चार फीसदी से अधिक परिवार कचरा बीनने, भीख मांगने और दान पर निर्भर है।

निस्संदेह, भारत के आर्थिक विकास का लाभ गांवों की तुलना में षहरों को अधिक मिला है। षहरों की चमक बढ़ती गई, पर गांवों में अनुकूल विकास नहीं हो पाया। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी कम होने और कृशि क्षेत्र में तेज विकास के कई दावे किए जाते हैं, मगर वास्तविकता इसके विपरीत है। हाल ही में मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने अपनी इंडिया रिपोर्ट में यह माना कि अर्थव्यवस्था में ग्रामीण भारत की हिस्सेदारी निराषाजनक है। इसके अनुसार, देष के ग्रामीण अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्श 2015–16 में कमजोर बनी रहेगी, जो भारत सरकार व देष के बैंकों की वित्तीय साख के प्रतिकूल है। अमेरिका की वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट में भी यह बताया गया है कि भारत में गांवों का समुचित विकास न होने का एक प्रमुख कारण कृशि आबादी में तेजी से वृद्धि होना है। साल 1980 से 2011 के बीच भारत की कृशक आबादी में भारी बढ़ोतरी हुई है।

रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया भर में कृशि आबादी सबसे ज्यादा भारत में ही बढ़ी है। कृशि पर निर्भर आबादी बढ़ने से इस क्षेत्र में लोगो की आय बढ़ने की बजाय घट रही है। इतना ही नहीं, गांवों में रोजगार के वैकल्पिक अवसर भी कम हैं। यही कारण है कि इस समय देष की 60 प्रतिषत आबादी रोजगार के लिए खेती–किसानी से जुड़ी हुई है, लेकिन सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कृशि क्षेत्र की हिस्सेदारी कम होती जा रही है। कृशि क्षेत्र का जीडीपी में जो योगदान आजादी के बाद करीब 50 फीसदी था, वह लगातार घटते हुए साल 2015 में महज 17 प्रतिषत रह गया है।

राश्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसओ) का कहना है कि 40 प्रतिषत किसान खेती को काफी जोखिम भरा और दुखदायी पेषा मानते हुए इसे छोड़ना चाहते हैं। सामाजिक–आर्थिक जनगणना के आंकड़े बता रहे हैं कि ऐसी निराषाजनक सोच के पीछे क्या असली कारण हैं। इस समय जरूरत है कि कृशि की उत्पादकता और इससे होनेवाले मुनाफे को तो बढ़ाया ही जाए, साथ ही गांवों में आजीविका के गैर–कृशि विकल्प भी तैयार किए जाऐं (भंडारी, 2015)।

कृशि अथवा खेतीबाड़ी भारतीय अर्थव्यवस्था की सदैव से रीढ़ रही है। हमारे देष में चलाई जा रही विभिन्न पंचवर्शीय योजनाओं के अन्तर्गत आने वाले अलग–अलग कार्यक्रमों द्वारा कृशि को राश्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एक गरिमापूर्ण स्थान मिला। देष में कृशि क्षेत्र की 62 प्रतिषत मांग ग्रामीण क्षेत्र से ही आती है। देष के कुल षुद्ध राश्ट्रीय उत्पादन में इसका 29 प्रतिषत हिस्सा है। इसके अतिरिक्त देष में होने वाले निर्यातों का बड़ा हिस्सा भी कृशि क्षेत्र से ही आता है। आज देष की 125 करोड़ से अधिक जनसंख्या में लगभग 70 करोड़ जनसंख्या कृशि पर निर्भर है और इस 70 करोड़ में से 30 करोड़ के लगभग अषिक्षित है और 30 करोड़ के 85 प्रतिषत व्यक्ति खेती करते हैं अतः इन्हें षिक्षित कर उपजाऊ खेती हेतु बहुविकल्पीय प्रणाली खोजनी होगी। यह भी एक सच है कि उत्पादन के नए–नए कीर्तिमान स्थापित करने के बावजूद यहां 300 मिलियन व्यक्ति बेरोजगार हैं। यह देष के लिए सबसे बड़ी चुनौती हैं। आज गांव का बेरोजगार युवक काम की तलाष में षहरों मे जाकर दर–दर की ठोकरें खा रहा है। ऐसी दषा में यह आवष्यक हो जाता है कि जो भी गांव से जुड़े नवयुवक हैं, उन के लिए कृशि पर आधारित रोजगार के नये साधन तैयार किए जाएं। इस संबंध में आवष्यकता है कि कृशि आधारित लघु उद्योगों और उनसे जुड़े रोजगारों को बढ़ावा दिया जाए।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की समस्याएंः बिहार के परिप्रेक्ष्य में

कृशि जगत का प्रत्यक्ष तथा प्रथम जीवनाधार है। यह मानवीय सभ्यता की पहल उपलब्धि रही है। इसकी बदौलत ही मनुश्य ने किसी अन्न, वस्त्र तथा आवास की "स्व–तंत्र" व्यवस्था कर अन्य प्राणियों से अपने को अलग किया। प्रकृति की सामान्य प्रक्रिया में किसी अन्न, फल या औशधि का बीज कहीं गिर जाना और समय पर अंकुरित हो जाना अनादि काल से जारी था और आज भी है, परन्तु मनुश्य ने जब अपनी इच्छा के अनुसार कोई बीज (या बीज समूह) किसी जगह विषेश को गोड़कर उसमें डाले–पटाये होंगे और उस बीज में अंकुरण आये होंगे तभी से कृशि–संस्कृति का प्रारम्भ हुआ होगा। अधिक बीजों के लिए बड़े खेत बने होंगे, दौनी के लिए खलिहान विकसित हुए होंगे, ढुलाई के लिए गाड़ी, भंडारण के लिए कोठी आदि अनेक कृशि–संस्कृति के अंग–उपांग विकसित हुए होंगे।

जिस कृशि संस्कृति ने मनुश्य को इस सृश्टि के सर्वश्रेश्ठ प्राणी के रूप में प्रतिश्ठित किया वह आज जनसंख्या–वृद्धि तथा मानव–समाज की अविवेकपूर्ण दोन–वृत्ति तथा उपेक्षा के कारण स्वयं दबाव में आ गयी है। इस स्थिति से कृशि को उबार कर सर्वांगपूर्ण सक्षम कृशि–संस्कृति की पुनर्प्रतिश्ठता के लिए बिहार राज्य में सुनियोजित कृशि रोड मैप का प्रारंभ किया गया। एक निष्चित काल खंडों के लिए निर्धारित इन योजनओं (रोड–मैप) का प्रारंभ से ही प्रयास रहा है कि कृशि के विकास के साथ ही कृशि संस्कृति के विनाष को रोकने के लिए आधुनिकतम वैज्ञानिक संसाधनों का भरपूर उपयोग करते हुए भी न प्रकृति के स्वाभाविक विकास–क्रम को बाधित किया जाय न उपज या दोहन में असंतुलन आने दिया जाय। यह कारण है कि रोड–मैप 2017–22 में मात्र अन्न और सब्जी–फल ही नहीं औशधीय पौधे–वृक्षों तथा पेड़–पौधों से युक्त वनों के समुचित विकास को भी पूरे महत्व के साथ सम्मिलित किया गया है।

कृशि व्यावसायिक में जुटे तमाम किसान फूड प्रोसेसिंग के जरिए मुनाफा कमा रहे हैं। ऐसे किसानन अपने बागवानी से तैयार होने वाले उत्पाद को प्रोसेसिंग के जरिए बाजार में उतारते हैं। कम लागत में षुरू होनेवाली यह प्रोसेसिंग इंडस्ट्री किसानों को भरपूर मुनाफा दे रही है। उदाहरण के तौर पर आंवले की खेती करने वाले तमाम किसान आंवले के तैयार होने वाले उत्पादन को प्रोसेसिग के बाद जब बाजार में उतारते हैं तो उन्हें उत्पाद की दो से तीन गुना अधिक कीमत मिलती है।

वास्तव में फूड प्रोसेसिंग देष की वो इंडस्ट्री है जिसमें सीधे तौर पर 16 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ है। भारत चीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य सामग्री उत्पादक देष है। कृशि उत्पादों को खाने लायक बनाने से लेकर सुरक्षित रखने और मार्केटिंग का काम, फूड प्रोसेसिंग (खाद्य संस्करण) के अंतर्गत आता है। उत्पादन, खपत, निर्यात और विकास के लिहाज से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री देष की पांचवीं सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। हालांकि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का दायरा बहुत बड़ा है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है खाद्य सामग्रियों और पेय पदार्थों को प्रोसेस्ड करके रखना लेकिन विभिन्न तरह की खेती करने वाले किसान इसे आसानी से अपना सकते हैं।

राजस्थान एवं पंजाब के तमाम किसानों ने समूह के जरिए प्रोसेसिंग कारोबार षुरू किया है। वे अपने खेत में तैयार होनेवाले उत्पाद को प्रोसेसिंग के बाद बाजार में उतारते हैं। जैसे बड़े पैमाने पर टमाटर की खेती करने वाले किसान केचप आदि तैयार कराते हैं। इसी तरह हरियाणा में कई किसानों ने ग्वारपाठा की प्रोसेसिंग मषीन लगा रखी है। वे अपने उत्पाद क साथ ही पड़ोसी किसानों के उत्पाद भी मषीन के जरिए प्रोसेसिंग करते हैं। ऐसे में उन्हें मषीन की लागत निकालने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगता है। इसी तरह दुग्ध सामग्री, फल और सब्जियों की प्रोसेसिंग, अनाज प्रोसेसिंग, मांस और पोल्ट्री प्रोसेसिंग सभी में अलग–अलग तरीके से कारोबार किया जा सकता है। हालांकि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बेहद बड़ी होने के बावजुद देष में कुल कृशि उत्पाद का महज दो फीसदी हिस्सा ही प्रोसेस्ड किया जाता है। एक जनवरी के मुताबिक डेयरी सेक्टर में उत्पादन का चालीस फीसदी से ज्यादा हिस्सा प्रोसेस किया जाता है। ये किसी एक सेक्टर में प्रोसेसिंग का सबसे बड़ा आंकड़ा है

दुनिया में पशुओं की सबसे बड़ी तादाद भारत में है। विष्व में पशुधन की आबादी का करीब 20 फीसदी भारत के पास है जिनमें सबसे ज्यादा तादाद है दूध देने वाली गाय औ भैंसों की। 1970 के दषक में दूध उत्पादन पर जोर देने के लिए देषभर में ष्वेत क्रांति नाम से मुहिम छेड़ी गई। आज करीब 100 मिलियन टन सलाना दूध उत्पादन कर भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देष बना हुआ है।

देष में दुग्ध उत्पादों की प्रोसेसिंग का करीब 15 फीसदी हिस्सा ही संगठित क्षेत्र के जरिए होता हैं बाकी प्रोसेसिंग में असंगठित क्षेत्र लगे हैं जिनमें स्थानीय किसान से लेकर स्थानीय कारोबारी तक षामिल हैं। उत्तर प्रदेष, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, महाराश्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेष में सर्वाधिक दूध तैयार होता है। जाहिर है कि इन राज्यों में दूध से बनने वाले तरह–तरह के उत्पाद भी बड़ी मात्रा में तैयार किए जाते हैं। देष में प्रोषेस्ड दूध के कारोबार में डेयरी को–ऑपरेटिव सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। मिल्क पाउडर, पैकेज्ड मिल्क, बटर, घी, चीज और आइस्क्रीम जैसे यहां के डेयरी उत्पादों की विदेषों में भी बड़ी मांग है। पिछले 12 सालों में डेयरी उत्पादों के निर्यात में सलाना औसतन 25 प्रतिषत की बढ़ोतरी देखी गई है।

विभाजित बिहार (षेश बिहार) में उद्योगों का सर्वथा अभाव है। षेश बिहार के आर्थिक विकास का मुख्य आधार कृशि का विकास है अतः कृशि उद्योग के विकास का मार्ग प्रषस्त करना आवष्यक है। विभिन्न फसलों के उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में खाद्य प्रसंस्करण की सम्भावना नव बिहार के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। फल एवं सब्जी के उत्पादन में बिहार का अग्रणी स्थान है। अविभाजित बिहार का देष में सब्जी के उत्पादन में द्वीतीय स्थान एवं फल में चौथा स्थान था। फलों में आम, केला, अन्नास, अमरूद, लीची, पपीता, नींबू युक्त फल प्रमुख हैं। राज्य के महत्वपूर्ण सब्जियों में आलू, बन्दगोभी, गोभी, बैंगन, टमाटर, भिंडी, प्याज, मिर्च आदि हैं जिनका उत्पादन बहुतायत में होता है। उत्पादकता के दृश्टिकोण से फलों में आय का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, लीची के उत्पादन में बिहार राज्य का एकाधिकार जैसा है। इन फसलों के उचित फसलोत्तर प्रबन्धन एवं प्रसंस्करण के द्वारा इनके उत्पादन एवं मूल्यों में गुणात्मक वृद्धि लाई जा सकती है जो न केवल कृशकों के लिए लाभदायक है बल्कि राज्य के आर्थिक विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है।

षेश बिहार में कई महत्वपूर्ण नगद फसलों का उत्पादन होता है जिसका औद्योगिककरण से पत्यक्ष सम्बन्ध है इन फसलों में जूट, ईख एवं तम्बाकू की खेती महत्वपूर्ण है। कई महत्वपूर्ण मसाला की फसलों जैसे हल्दी–मीर्च आदि का भी उत्पादन नव बिहार में होता है। किन्तु इन फसलों के भी उत्पादन में उपयुक्त रख रखाव एवं प्रसंस्करण के अभाव में अपेक्षाकृत वृद्धि नहीं हो पाई है। वस्तुतः इन फसलों के माध्यम से कृशि एवं उद्योग के बीच एक मजबूत कड़ी का निर्माण किया जा सकता था परन्तु कालान्तर में ऐसा नहीं हो सका। चीनी उद्योग उत्तर बिहार के औद्योगिकीकरण की रीढ़ कहा जा सकती है। अभी बिहार राज्य में 29 चीनी कारखानें स्थापित हैं जिसमें 18 चीनी निगम के माध्यम से सरकार द्वारा नियंत्रित हैं एवं 11 कारखानें निजी हैं। सरकार द्वारा नियंत्रित सभी मिलें या तो बन्द हैं या मृतप्राय हैं। निजी चीनी मिलों में मात्र चार ही ठीक से चल रहे हैं। कृशि एवं उद्योग के बीच मजबूत सम्बन्ध बनाने के लिए, ईख की खेती का समुचित विकास करना होगा एवं चीनी मिलों को इस प्रकार से कार्यरत बनाया जाए कि

ईख के उत्पादन में गुणात्मक वृद्धि किया जाए। उत्तर बिहार के सबसे बड़े औद्योगिक व व्यावसायिक केन्द्र मुजफ्फरपुर में फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योग अपेक्षित हैं। वर्श 2016 की औद्योगिक नीति में सब्सिडी खत्म होने के बाद फूड प्रोसेसिंग उद्योग को झटका लगा। इसके बावजूद औद्योगिक क्षेत्रों के अलावा उत्तर बिहार के प्रायः हर गली–मुहल्ले व गांवों में फूड प्रोसेसिंग इकाइयां तेजी से खुल रही हैं। छोटे, मझोले व बड़े को मिलाकर फिलहाल उत्तर बिहार में फूड प्रोसेसिंग की ढ़ाई हजार से अधिक इकाइयां चल रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि रोजगार मामले में ये इकाइयां वरदान साबित हो रही हैं। कम पूंजी के कारण मध्यम व गरीब वर्ग तेजी से इनसे जुड़कर काम कर रहे हैं।

उत्तर बिहार के जिलों के अधिकांष फूड प्रोसेसिंग इकाइयों में सत्तू, आटा, बेसन, चावल मिलों के अलावा पापड़, बड़ी, आचार, नमकीन, आइस्क्रीम आदि खाद्य पदार्थों का उत्पादन होता है। इसके अलावा जिले में दर्जन भर से ज्यादा मुर्गी व मवेषी दाना की कम्पनियां खुल चुकी हैं। पारले बिस्कूट के अलावा लिज्जत पापड की इकाई जिले में चल रही है। गली–मुहल्ले व गांवों में चल रहे फूड प्रोसेसिंग इकाइयों के बारे में उद्योग विभाग के पास अधिकारिक सूचना नहीं है, ले ये इकाइयों रोजगार सृजन के मामले में बड़े उद्यमियों से कहीं आगे हैं।

फल से जुड़े फूड प्रोसेसिंग उद्योग में लीची की बादषाहत है। लीची से तैयार होनेवाले पल्प, जूस व रसगुल्ला का बाजार विदेष तक फैला है। लीची नगरी मुजफ्फरपुर में लीची पर आधारित आधा दर्जनभर फूड प्रोसेसिंग इकाइयां चल रही है। सब्जियों में बात करें तो वहां के टमाटर की सबसे अधिक मांग है। लीची के बाद टमाटर का ही स्थान है। हाल के वर्शों में बियाडा के औद्योगिक क्षेत्रों के अलावा दूसरे इलाकों में टमाटर से जुड़ी दर्जनभर से ज्यादा इकाइयां खुली हैं। टमाटर का उपयोग सॉस बनाने में किया जाता है। इसके अलावा फलों में जैम बनाने वाली यूनिट भी चल रही है। इन इकाइयों के सामने बाजार बनाने की बड़ी चुनौती है। तमाम प्रयास के बावजूद स्थानीय फूड प्रोसेसिंग इकाइयां बजार नहीं बना सकी हैं। इस कारण इन इकाइयों में तैयार उत्पाद खपाने में दिक्कतें आती हैं। लिहाजा बड़ी बहुराश्ट्रीय कंपनियों की तुलना में स्थानीय फूड प्रोसेसिंग इकाइयों की विकास दर काफी धीमी है। इन्हें मदद मिले तो तरक्की की रफ्तार तेज हो सकती है।

पानी से निकाले जाने के बाद लगभग 10 प्रतिषत मछलियां तथा पककर तैयार होने के बाद 15 प्रतिषत से अधिक फल और सब्जियां, परिवहन सुविधाओं की कमी, प्रसंस्करण सुविधाओं के अभाव में तथा छंटाई एवं पैकेजिंग के दौरान नश्ट हो जाती हैं।

केन्द्रीय फसलोत्तर इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सीफेट) लुधियाना ने जल्द खराब होनेवाले कृशि उत्पादों पर पिछले वर्श एक अध्ययन किया जिसके अनुसार पानी से निकाले जाने के बाद 10.52 प्रतिषत मछलियां आधारभूत सुविधाओं के अभाव में नश्ट हो जाती हैं। इसी तरह पककर तैयार होने तथा पेड़ से तोड़ने के बाद 4.58 प्रतिषत से 15.88 प्रतिषत तक फल और सब्जियां खराब हो जाती हैं।

अनाजों में यह हानि 4.65 से 5.99 प्रतिषत, दालों में 6.36 प्रतिषत से 8. 41 प्रतिषत तथा तिलहनों में 3.08 से 9.96 प्रतिषत तक है। कुल मिलाकर सलाना 92,651 करोड़ रूपये तक की फसलोत्तर हानियां हैं। संसद कीी कृशि संबंधी स्थाई समिति ने हाल की अपनी एक रिपोर्ट में फसलों के तैयार होने के बाद नश्ट होने पर चिंता व्यक्त की है और इसे नियंत्रित करने के उपाय करने की सिफारिष की है। समिति ने कहा है कि अनाजों में यह हानि मुख्य रूप से फसल की पैदावार, एकत्रीकरण आदि के दौरान होती है जबकि फलों और सब्जियों में यह नुकसान अधिकतर उपज के दौरान होती हैं। इस नुकसान से पता चलता है कि सरकारी योजनाएं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समक्ष वर्शों से आ रही समस्याओं एवं चुनौतियों का समाधान नहीं कर पा रही हैं।

बिहार में मषरूम की खेती की अपार संभावनाएं हैं। कम लागत और अच्छा मुनाफा के कारण यहां के किसान इसकी खेती से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी बन सकेंगे। नालंदा, पूर्णिया, समस्तीपुर और बक्सर के किसानों का रूझान तेजी से मषरूम की खेती की ओर बढ़ रहा है। अगर किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए प्रषिक्ष और बाजार की व्यवस्था कर दी जाए तो बिहार इसकी पैदावार में अव्वल हो सकता है।

बिहार में प्रत्येक पंचायत में गोदाम का निर्माण किया जाना जरूरी है। राज्य में 8391 पंचायतें हैं। वहां दो सौ या पांच सौ मैट्रिक टन की क्षमता के गोदामों का निर्माण से किसानों को अधिक लाभ नहीं होगा। इसके लिए एक हजार मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम बनाये जाने चाहिए। पैक्स एवं व्यापार मंडलों के माध्यम से जो गोदाम बनाए जा रहे हैं उनकी क्षमता के विस्तार की भी जरूरत है। गोदाम व कोल्ड स्टोरेज जितना अधिक होगा राज्य के किसान उतने ही खुषहाल होंगे।

छोटे उद्योगों के विकास के लिए सिंगल विंडो सिंस्टम सबसे जरूरी है। आवेदक को आधार कार्ड पर सारी सुविधा दिए जाने के बाद नए उद्योग–धंधों की स्थापना में काफी सुविधा होगी। सिंगल विंडो सिस्टम नहीं रहने से विभिन्न चरणों से गुजर कर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का लाइसेंस निर्गत होता है। इससे उद्यमियों को नाकों चने चबाना पड़ता है। सिंगल विंडो सिस्टम अन्य राज्यों में लागू है। बिहार में इसके लागू हो जाने के बाद युवा उद्यमी निष्चित रूप से आगे आएंगे और वे बिहार के विकास के सहयोगी बनेंगे। सेल्स टैक्स विभाग द्वारा उद्योगों की स्थापना के लिए लगने वाली अग्रिम राषि को माफ कर देना चाहिए। इसके साथ ही षुरूआती पांच वर्शों के लिए भी टैक्स फ्री कर देना चाहिए ताकि नए उद्योग बेहतर तरीके से स्थापित हो सकें। बिहार में उद्योग–धंधों की भरपूर संभावना है और इसके लिए जरूरी है कि छोटे–छोटे उद्योगों के राश्ट्री स्तर पर प्रमोषन के लिए फ्री प्लेटफॉर्म की व्यवस्था की जाए। इन सारी चीजों के अलावा बिना नजायज राषि लिए हुए बिजली कनेक्षन देने और बिजली की निर्बाध आपूर्ति से उद्यमियों को बेहद फायदा होगा। औद्योगिक क्षेत्र में जमीन का सिंगल विंडो सिस्टम से सहज आवंटन हो। युवा उद्यमियों को प्रषासनिक मदद मिले। प्रखंड तथा अनुमंडल स्तर पर कृशि का प्रषासनिक तंत्र अभी भी सुसंगठित नहीं हुआ है। प्रखंड कृशि पदाधिकारी का प्रषासनिक नियंत्रण प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास होने के कारण प्रखंड कृशि पदाधिकारी गैर कृशि जिम्मेदारियों में ही अधिक संलग्न रहते हैं, जिससे कृशि का कार्य प्रभावित होता है। इसके प्रभावी सुधार की आवष्यकता है।

बिहार की खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की इकाइयों को बिजली की कमी के साथ क्वालिटी बिजली की चुनौती झेलना पड़ रहा है। बियाडा के तहत आने वाले औद्योगिक क्षेत्रों मं अलग से बिजली आपूर्ति की व्यवस्था अबतक नहीं हो पायी है। सिहायषी इलाकों की तरह फक्ट्रियों को भी बिजली की आंख मिचौली का सामना करना पड़ता है। बार–बार बिजली आपूर्ति ठप होने पर उत्पादन बाधित होता है। साथ ही मषीनों पर प्रतिकूल प्रभाव / असर पड़ता है। साथ ही क्वालिटी बिजली के अभाव में इकाइयों को लो वोल्टेज की कमी का सामना करना पड़ता है। उद्यमियों के आंदोलन के बावजूद इकाइयों के लिए अलग से बिजली की व्यवस्था नहीं हो पायी है।

मक्का, धान व केला के पैदावार में बिहार अग्रणी राज्यों की श्रेणी में षुमार है, लेकिन इन फसलों का उपयोग फूड प्रोसेसिंग के लिए नहीं हो पा रहा है। इसके कारण पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेष समेत दर्जन भर राज्यों के उद्यमी व व्यापार यहां से मक्का व धान की खरीददारी करते हैं। फिर वहां पर मवेषी दाना, मुर्गी दाना, चावल के अलावा ग्लूकोज आदि दवाइयां बनायी जाती है। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेष व उत्तरांचल ने चावल मिलों को प्रोत्साहित करने के लिए अनोखी पहल की है। वहां की सरकारें अब मिलरों से चावल खरीद रही हैं। धान की तरह सरकारें चावल का मूल्य तय करती हैं, जबकि यहां पर धान खरीदा जाता है। सरकार द्वारा चावल खरीदे जाने पर फूड प्रोसेसिंग इकाइयों को प्रोत्साहन मिलेगा। वहीं, गंगा व गंडक नदी के किनारे बसे जिले केला के मामले में अग्रणी है, लेकिन दक्षिण के राज्यों की तरह केला को फूड प्रोसेसिंग से जोड़ने के लिए अब तक पहल नहीं हुई है। केरल की तरह उत्तर बिहार में भी केला से चिप्स व अन्य उत्पाद तैयार हो सकते हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कच्चेमाल की समस्या, वित्त की समस्या, उत्पादन तकनीक की समस्या, विपणन की कठिनाइयां, बड़े उद्योगों से प्रतियोगिता, प्रमाणिकता का अभाव, सूचना एवं परामर्ष का अभाव, श्रम एवं कराधान का दोशपूर्ण होना, कृशि आधारित उद्योगों में रूग्णता, सरकारी संस्थाओं का नौकरषाही रवैया, प्रबंध क्षमता की समस्या, परिवहन साधन की कमी, उद्योगों के बीच आपसी समन्वय का अभाव, सस्ती चालन षक्ति की अपर्याप्तता, निर्यात की अपेक्षा, अनुसंधान की कमी इत्यादि से जूझ रहा है। भावी विकास की दृश्टि से इन पर ध्यान देने जरूरी है।

असंगठित इकाइयों को फलने–फूलने की दिषा में सार्थक प्रयास की आवष्यकता है। अधिकांष इकाइयां आज भी असंगठित रूप में कार्यरत

है। ऐसे में उद्यमिता विकास कार्यक्रम के निरन्तर आयोजन की महती आवष्यकता है। अध्ययन के क्रम में सामने आए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की प्रमुख चुनौतियां हैं :

- फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उत्पादों के लिए बाजार का आभाव,
- लीची की तुलना में अन्य फलों की कमी होना,
- फूड प्रोसेसिंग इकाइयों में विष्वस्तरीय तकनीक की कमी,
- उत्पाद तैयार करने वाले स्किल्ड कर्मियों का न होना,
- नए उद्यमियों को इकाई लगाने के लिए पूंजी का आभाव,
- सरकार की ओर से मिलने वाली प्रोत्साहन की कमी,
- क्वालिटी व निर्बाध बिजली आपूर्ति की कमी,
- पैकेजिंग और बार कोड से जुड़ी संसाधनों का संकट,
- सरकारी संस्थाओं का नौकरषाहीी रवैया इत्यादि।

निश्कर्श

आजादी के समय देष की जो जनसंख्या 38 करोड़ के आसपास थी वह आज सवा अरब के करीब पहुंच गई है। ऐसी स्थिति में चाहे सरकारी क्षेत्र हो, सार्वजनिक क्षेत्र या फिर निजी क्षेत्र, अकेले कोई भी रोजगार की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। मौजूदा हालात में तो ये तीनों क्षेत्र मिलकर भी देष की एक बहुत छोटी आबादी को ही रोजगार उपलब्ध करवाने में सक्षम हैं। नतीजतन बढ़ती आबादी के बाद रोजगार की अनुपलब्धता देष की दूसरी सबसे बड़ी समस्या बन गई है। यह एक बहुत बड़ी विडम्बना है कि देष का तेजी से आर्थिक विकास हो रहा है लेकिन यहां का बहुत बड़ा तबका इस विकास का हिस्सा नहीं है। यहां की आबादी का बहुत बड़ा भाग अभी भी दो वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है। तेजी से हो रहे आर्थिक विकास से किसी को भी कोई षिकायत नहीं हो सकती लेकिन ऐसे में इस तरक्की के क्या मायने कि जब देष में बहुत से लोग या तो भूखमरी के षिकार हैं या फिर भूख से तंग आकर आत्महत्या करने को मजबूर हैं। देष के किसान अपनी जीवन–लीला समाप्त कर रहे हैं, यह भी एक वास्तविकता है। ऐसी परिस्थितियों में लोगों के आर्थिक स्तर को उठाने के प्रयास अपेक्षित हैं। रोजगार के विभिन्न अवसर उपलब्ध करवा कर निष्चित ही लोगों के आर्थिक स्तर को उठाकर आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। इस दिषा में कृशि पर आधारित उद्योगों को विकसित कर उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।

भौतिक विविधताओं से भरा बिहार एक कृशि प्रधान राज्य है। यहाँ की 75 प्रतिषत जनता कृशि पर आश्रित है। आज भी कृशि आधारित उद्यमों जैसे, फल–सब्जियों का प्रसंस्करण, नर्सरी व्यवसाय, बड़े स्तर के चावल, दाल, आटा, सूजी, मैदा, मसाला, तेल, पापड़, चूड़ा, बिस्कूट निर्माण आदि की इकाईयों का आभाव है। आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले कृशि यंत्रों के निर्माण के लिए यहाँ उद्योग स्थापित किये जाने की आवष्यकता है। मधु उत्पादन के क्षेत्र में बिहार अन्य राज्यों की तुलना में अग्रणी है, फिर भी मधु प्रसंस्करण एवं निर्यात की कोई बड़ी इकाई स्थापित नहीं हो सकी है। राज्य सरकार द्वारा पुरानी चीनी मिलों को सुधारने एवं कुछ नयी चीनी मिल स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। कृशि आधारित उद्योगों के विकास से न केवल रोजगार के अधिक अवसर का सृजन होता है बल्कि फसलों के विक्रय को स्थिर रखने में सहायता मिलती है।

बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की असीम संभावनाएं हैं लेकिन इन संभावनाओं के दोहन के लिए कई चुनौतियों पर विजय प्राप्त करनी होगी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की राह की प्रमुख बाधाएँ उत्पादों के लिए बाजार का अभाव, विष्वस्तरीय तकनीक की कमी, उत्पाद तैयार करने वाले कुषल कर्मियों की कमी, पूंजी का अभाव, सरकारी प्रोत्साहन की कमी, निर्बाध बिजली की आपूर्ति का न होना, परिवहन सुविधाओं का अभाव, पैकेजिंग और बार कोड से जुड़ी संसाधनों का संकट इत्यादि हैं। इन समस्याओं के निराकरण से बिहार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का हब बन सकता है। परिणामस्वरूप रोजगार एवं आय में वृद्धि होगी और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य में आर्थिक क्रांति लाने में सफल होगी।

सन्दर्भ सूची

1. द्विवेदी, कल्पना (2014), भारतीय अर्थव्यवस्था में कृशि आधारित उद्योगों की भूमिका, कुरूक्षेत्र, वर्श 60, अंक 7, मई
2. भंडारी, जयंतीलाल (2015), खुषहाली से बहुत दूर है गांव की यह तस्वीर, संपादकीय पन्ना, हिन्दुस्तान, पटना संस्करण, 6 जुलाई
3. विनम्र, गौरीषंकर वैष्य (2014), भारत में कृशि से जुड़े नए उद्योग–धंधे, कुरूक्षेत्र, वश–60, अंक – 7, मई
4. श्रीवास्तव, मनोज (2015), कृशि के व्यवसायीकरण में कांट्रैक्ट फार्मिंग, कुरूक्षेत्र, वर्श 61, अंक 3, जनवरी
5. हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर, सोमवार, 22 मई 2017
6. सोलंकी, अर्जून (2014), कृशि आधारित प्रमुख उद्योगः समस्या एवं सुझाव, कुरूक्षेत्र, वर्श 60, अंक 7, मई
7. पाण्डेय, जितेन्द्र कुमार (2014), कृशि का व्यासायीकरण जरूरी, कुरूक्षेत्र, वर्श 60, अंक 7, मई